कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना

कृषि कुंभ (जुलाई 2023),
खण्ड 03 भाग 02, पृष्ठ संख्या 137–139

कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना

आशीष कुमार वर्मा[1], अमन वर्मा[2] एवं श्याम नारायण पटेल[3],
[1]शोध छात्र (सस्यविज्ञान), [2]शोध छात्र (कृषि प्रसार शिक्षा),
[3]शोध छात्र (पादप रोग विज्ञान),
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत।
Email Id: ashishverma9787@gmail.com

परिचय

कृषि वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए भोजन, कच्चा माल और रोजगार के अवसर प्रदान करती है। हालाँकि, कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना किसानों और क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। बाजार की कीमतों में उतार–चढ़ाव, इनपुट लागत, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और संसाधनों तक सीमित पहुंच जैसे कारक लाभप्रदता में बाधाएं पैदा कर सकते हैं। इन चुनौतियों से पार पाने और कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, ऐसी रणनीतियों और प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है जो किसानों की आय बढ़ाएं, उत्पादकता में सुधार करें और टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा दें।

इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें अन्य कारकों के अलावा बाजार–उन्मुख उत्पादन, कुशल संसाधन प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला अनुकूलन और वित्त तक पहुंच शामिल हो।इन रणनीतियों को लागू करके, किसान अपनी लाभप्रदता में सुधार कर सकते हैं, आर्थिक झटकों के प्रति अपनी लचीलापन बढ़ा सकते हैं और ग्रामीण समुदायों के समग्र आर्थिक विकास और विकास में योगदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है, गरीबी कम करती है, और ग्रामीण रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा करती है। इस चर्चा में, हम कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए किए जा सकने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों और पहलों का पता लगाएंगे। इनमें बाजार–उन्मुख उत्पादन, मूल्य श्रृंखला अनुकूलन, कुशल संसाधन प्रबंधन, वित्त और ऋण तक पहुंच, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे का विकास, विविधीकरण और मूल्य संवर्धन, बाजार सूचना और प्रौद्योगिकी और नीति समर्थन शामिल हैं।

कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना क्यों महत्वपूर्ण है?

कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना कई कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है:

खाद्य सुरक्षा: कृषि विश्व स्तर पर खाद्य उत्पादन का प्राथमिक स्रोत है। पर्याप्त खाद्य आपूर्ति बनाए रखने और बढ़ती वैश्विक आबादी को खिलाने की चुनौती से निपटने के लिए इसकी आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। जब कृषि आर्थिक रूप से व्यवहार्य होती है, तो किसान उत्पादकता बढ़ाने, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और उन प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं जो खाद्य उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ा सकते हैं।

आर्थिक विकास: कृषि कई देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेषकर विकासशील देशों में। जब कृषि आर्थिक रूप से व्यवहार्य होती है, तो यह कृषि उत्पादन, कृषि–प्रसंस्करण उद्योगों और निर्यात अवसरों में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक विकास में योगदान देती है। एक जीवंत कृषि क्षेत्र संबंधित उद्योगों और क्षेत्रों को उत्तेजित करता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ता है।

वैश्विक व्यापार और प्रतिस्पर्धात्मकता: आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि वैश्विक बाजार में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है। जब किसान कुशलतापूर्वक और लाभप्रद रूप से कृषि उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं, तो यह उच्च गुणवत्ता वाले सामानों के निर्यात की अनुमति देता है, इस प्रकार विदेशी मुद्रा आय में योगदान देता है और वैश्विक व्यापार में देश की स्थिति को मजबूत करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच से किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है और समग्र आर्थिक स्थिरता में योगदान हो सकता है।

नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाना: आर्थिक व्यवहार्यता किसानों को नवाचार को अपनाने और आधुनिक प्रौद्योगिकियों

को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। नई कृषि पद्धतियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के वित्तीय साधनों के साथ, किसान उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं, संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित कर सकते हैं और समग्र दक्षता बढ़ा सकते हैं। यह कृषि नवाचार को बढ़ावा देता है और समग्र रूप से क्षेत्र की उन्नति में योगदान देता है।

क्या हैं चुनौतियां

ऐसी कई चुनौतियाँ हैं जो कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता में बाधा बन सकती हैं। ये चुनौतियाँ क्षेत्र, कृषि प्रणाली और विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं, लेकिन कुछ सामान्य चुनौतियों में शामिल हैं:

बाजार की कीमतों में उतार–चढ़ाव: कृषि अस्थिर बाजार स्थितियों के अधीन है, जहां कृषि वस्तुओं की कीमतों में काफी उतार–चढ़ाव हो सकता है। किसानों को अक्सर बाजार मूल्य परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने और प्रतिक्रिया देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी लाभप्रदता और आय को प्रभावित कर सकता है।

इनपुट लागत: बीज, उर्वरक, कीटनाशक और मशीनरी जैसे कृषि इनपुट की लागत महत्वपूर्ण हो सकती है। किसानों को इन इनपुटों को वहन करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, खासकर बढ़ती इनपुट कीमतों के दौरान। उच्च इनपुट लागत लाभ मार्जिन को कम कर सकती है और आर्थिक व्यवहार्यता हासिल करना चुनौतीपूर्ण बना सकती है।

जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ: जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जैसे चरम मौसम की घटनाएँ, सूखा, बाढ़ और कीट और बीमारियाँ, कृषि के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करते हैं। इन घटनाओं से फसल बर्बाद हो सकती है, उपज में कमी हो सकती है और उत्पादन लागत बढ़ सकती है, जिससे किसानों की लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है और कृषि आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

सीमित बाजार पहुंच: परिवहन लागत, बाजार की जानकारी की कमी, व्यापार नियमों और गुणवत्ता और प्रमाणन आवश्यकताओं जैसी बाधाओं के कारण किसानों को स्थानीय, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सीमित बाजार पहुंच किसानों की अपनी उपज को अनुकूल कीमतों पर बेचने की क्षमता को बाधित कर सकती है, जिससे आर्थिक व्यवहार्यता कम हो सकती है।

सीमित तकनीकी ज्ञान और कौशल: प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और ज्ञान संसाधनों तक पहुंच की कमी किसानों की आधुनिक कृषि पद्धतियों, नवीन प्रौद्योगिकियों और मूल्य वर्धित गतिविधियों को अपनाने की क्षमता में बाधा बन सकती है। अपर्याप्त तकनीकी ज्ञान और कौशल उत्पादकता सुधार और लाभप्रदता को सीमित कर सकते हैं।

बाजार में अस्थिरता और मूल्य जोखिम प्रबंधन: बाजार की स्थितियों में उतार–चढ़ाव के कारण किसानों को अक्सर मूल्य जोखिम का सामना करना पड़ता है। प्रभावी मूल्य जोखिम प्रबंधन तंत्र की कमी, जैसे कि हेजिंग विकल्प या फसल बीमा, किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं और वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार ने क्या पहल की है?

दुनिया भर की सरकारों ने कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल लागू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य किसानों का समर्थन करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, बाजार पहुंच में सुधार करना और कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। यहां सरकारों द्वारा की गई कुछ सामान्य पहल हैं:

कृषि सब्सिडी और सहायता कार्यक्रम: सरकारें सब्सिडी, अनुदान और प्रत्यक्ष भुगतान के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। ये कार्यक्रम किसानों को उत्पादन लागत से निपटने, इनपुट खरीदने और बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और मशीनरी में निवेश करने में मदद करते हैं। सब्सिडी विशिष्ट फसलों, क्षेत्रों या कृषि उत्पादन के पहलुओं, जैसे सिंचाई या जैविक खेती को लक्षित कर सकती है।

मूल्य समर्थन तंत्र: सरकारें कृषि वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने और किसानों को मूल्य अस्थिरता से बचाने के लिए मूल्य समर्थन तंत्र लागू करती हैं। इन तंत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) शामिल हो सकते हैं, जहां सरकार चयनित फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देती है, या बाजार में गिरावट के दौरान कीमतों को स्थिर करने के लिए कमोडिटी बाजार में हस्तक्षेप करती है।

कृषि ऋण और वित्तीय सहायता: सरकारें कृषि ऋण, माइक्रोफाइनेंस पहल और क्रेडिट गारंटी योजनाओं जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के लिए ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती हैं। ये पहल किसानों को अपनी कृषि गतिविधियों में निवेश करने, इनपुट

खरीदने और वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाती हैं।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकासः सरकारें कृषि उत्पादकता और बाजार पहुंच में सुधार के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करती हैं। इसमें सिंचाई प्रणाली, ग्रामीण सड़कें, भंडारण सुविधाएं, बाजार यार्ड और कोल्ड चेन का निर्माण शामिल है। बेहतर बुनियादी ढाँचा कृषि वस्तुओं की कुशल आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है, फसल के बाद के नुकसान को कम करता है और बाजार कनेक्टिविटी को बढ़ाता है।

बाजार संपर्क और मूल्य श्रृंखला विकासः सरकारें उन पहलों का समर्थन करती हैं जो कृषि में बाजार संपर्क और मूल्य श्रृंखला विकास को मजबूत करती हैं। इसमें किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना करना, अनुबंध खेती की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना, कृषि–प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना और थोक बाजारों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों जैसे बाजार बुनियादी ढांचे का निर्माण करना शामिल है।

बीमा और जोखिम प्रबंधनः सरकारें किसानों को उत्पादन जोखिमों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए फसल बीमा कार्यक्रमों और जोखिम प्रबंधन उपकरणों को बढ़ावा देती हैं। मौसम–अनुक्रमित बीमा, राजस्व–आधारित बीमा, और पैरामीट्रिक बीमा योजनाएं किसानों को जलवायु परिवर्तनशीलता, कीट और बीमारी के प्रकोप और बाजार में उतार–चढ़ाव से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद करती हैं।

कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए कुछ नीतिगत विकल्प क्या हैं?

कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए सरकारें विभिन्न नीतिगत विकल्प लागू कर सकती हैं। इन नीतियों का उद्देश्य किसानों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, बाजार तक पहुंच बढ़ाना और कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। यहां कुछ नीतिगत विकल्प दिए गए हैं जो कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता में योगदान दे सकते हैं:

मूल्य समर्थन और स्थिरीकरण तंत्रः किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जैसे मूल्य समर्थन तंत्र स्थापित कर सकती हैं। मूल्य अस्थिरता को कम करने और किसानों को बाजार के उतार–चढ़ाव से बचाने के लिए स्थिरीकरण निधि या बाजार हस्तक्षेप कार्यक्रम भी लागू किए जा सकते हैं।

सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहनः सरकारें कृषि गतिविधियों का समर्थन करने के लिए किसानों को लक्षित सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं। इनमें बीज, उर्वरक और मशीनरी जैसे इनपुट के लिए सब्सिडी, साथ ही टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, या जलवायु–स्मार्ट कृषि तकनीकों को लागू करने के लिए प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं।

कृषि बीमा और जोखिम प्रबंधनः सरकारें किसानों को उत्पादन जोखिमों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए फसल बीमा कार्यक्रमों और जोखिम प्रबंधन उपकरणों को बढ़ावा दे सकती हैं। मौसम–अनुक्रमित बीमा, राजस्व–आधारित बीमा और पैरामीट्रिक बीमा योजनाएं किसानों को जलवायु परिवर्तनशीलता, कीटों, बीमारियों और बाजार में उतार–चढ़ाव से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद कर सकती हैं।

बुनियादी ढाँचा विकासः कृषि उत्पादकता और बाजार पहुँच में सुधार के लिए सरकारें ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश कर सकती हैं। इसमें सिंचाई प्रणाली, ग्रामीण सड़कें, भंडारण सुविधाएं, बाजार यार्ड और कोल्ड चेन का निर्माण और रखरखाव शामिल है। बेहतर बुनियादी ढाँचा कृषि वस्तुओं की कुशल आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है, फसल के बाद के नुकसान को कम करता है और बाजार कनेक्टिविटी को बढ़ाता है।

अनुसंधान और विकासः सरकारें नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने के लिए कृषि अनुसंधान संस्थानों और विस्तार सेवाओं को संसाधन आवंटित कर सकती हैं। अनुसंधान एवं विकास में निवेश उन्नत फसल किस्मों, टिकाऊ कृषि पद्धतियों, कुशल सिंचाई प्रणालियों और जलवायु–स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

बाजार पहुंच और मूल्य श्रृंखला विकासः सरकारें उन पहलों का समर्थन कर सकती हैं जो कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच और मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ाती हैं। इसमें किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना, अनुबंध खेती की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना, कृषि–प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना और थोक बाजारों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों जैसे बाजार के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना शामिल हो सकता है।